

# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 66/2018

बउनवान

ज्ञानचन्द आयु 30 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति—बैरवा निवसी—निमोदा  
तहसील—पीपल्दा जिला—कोटा

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे नायब तहसीलदार, मॉंगरोल

(रेस्पॉण्डेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पॉण्डेंट)

निर्णय दिनांक— 08.10.2018



अपीलांट ने जर्गे अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉंगरोल के आदेश दिनांक 31.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बमोरीकलां, तहसील—मॉंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.40 हैक्टर किरम चारगाह पर अतिक्रम मानकर 480/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन(तीन माह) के सिविल कारावास की सजा से सजा दिया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी पर अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है उसके विरुद्ध गलत रूप से कार्यवाही की गयी है। आदेश पारित करने के बाद अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, अपीलांट की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये एकतरफा कार्यवाही की गयी है। न्यायालय की पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई भी अधिनियम विरुद्ध पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.1.2018 निरस्त फरमाया जाये।

अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉण्डेंट को जर्गे सम्मन तलब किया गया है। अपील का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किया है। एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट को आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी है। अपीलांट को आराजी से कब्जा छोड़ दिया है।

**सत्यमेव जयते**

**Web Copy - Not Official**

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ ही कथन किया कि अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 40/2017 निर्णय दिनांक 25.02.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभावक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमी करने पर मिसल नम्बर 40/17 निर्णय दिनांक 25.02.2017 से बेदखल किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप अपील खारिज की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के निर्णय को चुनौती देना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट को अतिक्रमी माने जाने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 18/2018 में पारित आदेश दिनांक 31.1.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.1.2018 को जजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



सत्यमेव जयते (डॉ०एस.पी.सिंह)

Web Copy - Not Official

